लखनऊ से प्रकाशित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

6AM न्यूज टाइम्स

RNI N0.- UPHIN/2017/ 75301

27 मई, दिन शुक्रवार 2022

Email-
6amnewstimes2188@gmail.com

बहुत हुआ सत्ता परिवर्तन हमें चाहिए व्यवस्था परिवर्तन

OBC, SC/ST MONORITY की सम्मानजनक भागीदारी

या अबकी बार NOTA की होगी तैयारी

ना रोजगार की संभावना।
ना समुचित शिक्षा व्यवस्था।
ना उचित स्वास्थ्य व्यवस्था।

ना मान-सम्मान।
ना आरक्षण का मिला लाभ।
ना सुरक्षित माहौल का भरोसा।

दलित पिछड़ों के मुद्दों पर समाज के नेताओं
की खतरनाक चुप्पी का राज ।

व्यवस्था परिवर्तन के योद्धा
आज सत्ता परिवर्तन के बंधुआ मजदूर क्यु ।

सामाजिक न्याय के अघोषित दुश्मनों का विरोध
ही समाजिक हितों की रक्षा का एक मात्र रास्ता है।

सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक अधिकार रक्षा मोर्चा।

2

कजीवाड़ा: तैकड़ों बैंकिंग शिटकों की चली जाएगी नौकरी

6

टीम इंडिया के किस खिलाड़ी में कितना दम, अब सबका होगा डीएनए टेस्ट!

8

बंटी को दोस्त के साथ सोने के लिए कहता था एक्स बॉयफ्रेंड

6 एएम न्यूज टाइम्स

हिन्दी दैनिक

वर्ष-1, अंक-1 (प्रवेशांक) | लखनऊ से प्रकाशित लखनऊ, सोमवार, 13 नवम्बर, 2017 | पृष्ठ-8 मूल्य-2 रुपये

संक्षिप्त समाचार

नीतीश ने बिहार में घोटालों की भारी तेल लगाई हुई है: लालू

पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार में राजग द्वारा घोटालों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार में घोटालों की भारी 'सेल' लगा रखी है। लालू ने ट्वीट कर आरोप लगाया, नीतीश ने बिहार में घोटालों की भारी सेल लगाई हुई है। एक घोटाला करने पर तीन घोटाले करने की छूट है। ट्वीट के अलावा लालू ने पूछा है कि क्या आडवाणी नीतीश ने किसी खेरे कर्मचारी को तोड़कर किसी 'बड़ी मछली' पर कोई कार्रवाई की है।

माफिया-नेता संबंधों पर वोहरा समिति का संलग्नक रिकॉर्ड में नहीं: गृह मंत्रालय

नयी दिल्ली। संगठित आपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए 1993 में गठित एन एन वोहरा समिति की रिपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अस्तित्व में नहीं है। एक आरटीआई आवेदन दायर किए जाने के बाद यह जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस कोष्ठ में सूचना शामिल करने के लिए उसकी ओर से दायर आरटीआई आवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय के कई विभागों में दो वर्षों तक घूमता रहा और इस विभाग उन्हें नहीं कहा कि इससे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सोसी ने सभी संबंधितों और नोट शीट के साथ समिति को रिपोर्ट सौंपी थी। आवेदन जिस विभाग में है उसमें सूचना एकत्र की जाए और यह सूचना मांगने वाले को प्रदान की जाए इस मिशन के बावजूद संबंधित विभाग ने जवाब दिया कि उसके पास ऐसी रिपोर्ट है, लेकिन कोई संलग्नक और नोट शीट उपलब्ध नहीं है।

जनरल डिब्बे में मनचलों ने छेड़ा, रेप से बचने के लिए चलती ट्रेन से कूदी मां-बेटी

जयपुर। पुणे के कानपुर के पास दौड़ती ट्रेन में रेप की कोशिश को नाकामयाब करने की खबर आई है। बदमाशों के चंगुल फंसी मां और बेटी ने ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी इज्जत बचाई है। इस घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दे दी गई है। पुलिस कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। पीड़िता मां-बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 वर्षीय मां अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता से दिल्ली आ रही थी।

यूपी निकाय चुनाव

भाजपा ने फ्री वाई-फाई, 'पिंक' शौचालय का किया वादा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें जनता से प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में जो वाई-फाई, महिलाओं के लिए 'पिंक शौचालय' तथा कचरे प्लांट में सुअर जलापूर्ति आदि ऐसे का वादा किया है। इन चुनावों को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा माना जा रहा है। उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर यह संकल्प पत्र जारी किया।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र जारी करने के दौरान कहा 'पेटपास' के पासवर्ड सेवार्थ प्रदान करने की बात कही। राज्य की उन्होंने नौकायनों और अन्य पहुंचों के लिए भी आवश्यक स्थानों के बारे में कहा। भाजपा, विपक्षी दलों ने इस संकल्प पत्र को छलावा करार दिया। सपा ने संकल्प पत्र को 'छल पत्र' बताया वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर पुराने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। राज्य भर के 652 स्थानीय निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं, जो 2018 तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 16 नगर निगम शामिल हैं। इससे पहले राज्य में 12 नगर निगम थे। योगी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आरोपित और संदूषण प्रदूषण का पक्ष प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया और यहां पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जारी संकल्प पत्र में 28 संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें पूरा करने का वादा किया गया है। भाजपा सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि उसका लक्ष्य जनता की सेवा करना है।

कृष्णा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 16 लोगों की मौत, 7 लापता

एजेंसी

अमरावती। करीब 30 लोगों को लेकर जा रही एक नाव रविवार शाम को विजयवाड़ा के समीप कृष्णा नदी में डूब गई जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य लापता हैं। स्थानीय मछुआरों ने 15 लोगों को बचा लिया। मृतकों में छह महिलाएं और चार बच्चे हैं। बताया जाता है कि यह नौका एक निजी कंपनी द्वारा प्रायोजित पैसे पर चलाई जा रही थी। लापता लोगों की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल (एनडीआरएफ) की टीमें और कृष्णा जिला प्रशिक्षकारियों ने तलाश एवं बचाव अभियान चलाया है। प्रत्यक्ष दर्शी घूमा अधिकारी जिले ने पहले की जांच के बाद साथ अपने विभाग के अधिकारियों को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि क्या नौका संचालक ने आवश्यक अनुमति ली थी।

पुलिस ने बताया कि नौका पवित्र संगम से विजयवाड़ा के समीप कैरी गांव के पवित्र संगम के लिए रवाना हुई लेकिन यह डूबकर हो गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया नौका में क्षमता से अधिक 48 लोग सवार थे और ज्यादातर के पास लाइफ जैकेट नहीं थे। नौका चक्रिक संगम के पास एक चट्टान से टकरा गई। ज्यादातर लोग तैरकर किनारे पर आ गए। बताया जाता है कि ज्यादातर यात्री प्रकाशम जिले के ओंगोल जाकर कलम के कारण थे। कुछ यात्री गोलवेर के थे जो विजयवाड़ा जा रहे थे। जिले गांव से स्थानीय मछुआरों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए 15 लोगों को बचा लिया। बाद में 16 शव नदी से निकाले गए। एनडीआरएफ के 30-30 कर्मियों के दो दल राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का 45 सदस्यीय एक दल तथा आपदा प्रतिक्रिया दल दमकल सेवा विभाग का 60 सदस्यीय दल बचाव अभियान में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री एन किन राजन्ना, जिला के नेता वाई एस जगनमोहन रेड्डी तथा अन्य ने हादसे को लेकर अफसोस जाहिर किया है।

अरुणाचल पर किसी दूसरे के रुख को लेकर चिंतित नहीं: सीतारमण

एजेंसी

अहमदाबाद। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश को उसकी साफ पर चीन की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य भारतीय क्षेत्र है और इस पर किसी दूसरे के विचार से देश की कोई चिंता नहीं है। सीतारमण ने शनिवार और रविवार को इस सीमाई राज्य की पहली यात्रा की थी जिस पर चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि विवादित क्षेत्र की उसकी यात्रा क्षेत्र की स्थिति को ठीक नहीं है। इस पर भारत ने चीन की आपत्ति को खारिज करते हुए जोर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन को आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, क्या समस्या है? हम यहां जाएंगे। गुजरात में होने वाले चुनाव के सिलसिले में भाजपा के उम्मीदवार नीलाबेन चौहान की सभा में सीतारमण ने कहा, इस पर हमें किसी दूसरे को राय देने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री ने रक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीन को सीमा से लगे अगला जिले में आठवां सीमा चौकियों का दौरा किया था।

मप्र में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत

भोपाल। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के चित्रकूट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की। इससे पहले यह सीट पर भाजपा काबिज थी। इस सीट पर भाजपा की सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार नीलांशु चतुर्वेदी ने अपने निकटतम उम्मीदवार भाजपा की शकुन्तला खटीक को 14,133 वोटों के अंतर से हरा दिया। कांग्रेस उम्मीदवार को 66,810 वोट हासिल हुए तथा भाजपा प्रत्याशी खिलाड़ी को 52,677 वोट मिले।

मोदी आसियान समिट में शामिल होने पहुंचे फिलीपींस

एजेंसी

मनीला (फिलीपींस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये तीन दिन की यात्रा पर पहुंचे। अपने इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आतंकवाद और उग्रवाद की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये एक टैक्टिकल ट्रेनिंग तंत्र बिल जाने की भारत की मांग दोहराने के साथ क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाने के लिये कदम उठाने पर जोर दे सकते हैं।

वहां राजनीतिकों ने बताया कि मंगलवार को आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान विवादास्पद दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीनी की आक्रामक सैन्य गतिविधियों, उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल परीक्षणों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आसियान राष्ट्रीय ट्रेनिंग्स टूर, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकॉम टर्नबुल और रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव और कुछ अन्य देशों के नेताओं के साथ अलग से द्विपक्षीय मुलाकातें कर सकते हैं। इस प्रमुख देशों का संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की बैठक में भाग लेने के लिये भारत की पेशा आर्थ साथ ही, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयोथ रयनाक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियान लूंग और ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। पार और निवेश के साथ सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर के साथ भारत और आसियान के बीच संबंध पिछले कुछ साल में मजबूत हो रहा है। फिलीपींस में भारत के राजदूत जयदीप मजूमदार ने कहा, आसियान का प्रमोद देश चाहता है कि भारत हर संभव तरीके से क्षेत्र से जुड़े। यह एक वास्तविक गठजोड़ है ... अमेरिका, चीन और जापान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चात-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक रिजन) में भारत की बढ़ी भूमिका को सकारात्मक देखते हैं। चीन इस क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

खेमका का एक और तबादला, 52 की उम्र में इस अफसर का 54वां ट्रांसफर

एजेंसी

नई दिल्ली। हरियाणा के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का एक बार फिर तबादला कर दिया गया। यह उनका रिकॉर्ड 54वां ट्रांसफर है। इस बार उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से हटाकर खेल एवं युवा मामले विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। खास बात यह है कि खेमका अब खेल मंत्री अनिल विज के विभाग का जिम्मा संभालेंगे। विज खेमका के काम से खुश रहे हैं। उन्होंने कई बार खेमका की तारीफ की है। खेमका के अलावा हरियाणा सरकार ने 13 और आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका की गिनती बेदाग ईमानदार अधिकारियों में होती है। वे जिस विभाग में रहे, वहां अनियमितताओं का खुलकर विरोध किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे।

कोहरे के साथ ठंड बढ़ी, पारा 8.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

एजेंसी

लखनऊ। पूर्वानुमानों के मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। रविवार का दिन अब तक का इस मौसम सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान यहां 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसी ठंड दिनों से तापमान पड़ रही कोहरे का असर कम नहीं हो रहा है। कोहरे ने ट्रेन और यातायात को रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिए हैं। लगातार ट्रेन लेट चल रही है। रात और सुबह के समय सड़कों पर वाहनों रेंग रहा है। रविवार को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आसमान में सुबह नौ बजे के बाद ही प्रार्थना हो पाया। कोहरे के साथ मौसम भी काफी ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान यहां 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी जारी, अब तक 33 की मौत

एजेंसी

जयपुर। राजस्थान में पिछले चार दिनों से चिकित्सकों की हड़ताल से मेडिकल इमरजेंसी जारी है। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हो गई हैं। मरीजों को लाचार छुट्टी देकर घर भेजा जा रहा है। प्रदेशभर में 33 लोगों की मौत चिकित्सा के अभाव में हो चुकी है। सरकार और चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों के बीच वार्ता का दौर रविवार को एक बार फिर शुरू हुआ। अधिकारियों ने सहमति बन गई है। केवल चिकित्सकों की दो बड़ी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। चिकित्सक चाहते हैं कि 24 घंटों की सरकारी सेवा पूरी होने पर उन्हें अधीक्षक अधिकारियों के समान ग्रेड पे दिया जाए। साथ ही एक पाली में अधिकतम पचास लोगों को परीक्षण करने की अनुमति दी जाए।

सरकार इन दोनों ही मांगों को मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि एक पाली में अधिकतम पचास से सौलोगों को परीक्षण करने की अनुमति देने से मरीजों को परेशानी होगी।

सीबीआई : प्रद्युम्न मर्डर केस में पुलिस ने की सबूत मिटाने की कोशिश

एजेंसी

नई दिल्ली। गुरुग्राम के रेयान स्कूल में हुए प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने कई सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। इसके बाद बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह खुलासा सीबीआई सूत्रों के जरिए हुआ है।

इस मामले में 8 दोषों के खुलासे के बाद से ही पुलिस जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि गुरुग्राम पुलिस ने जांच कंडक्टर अशोक कुमार को दूसरे कबूल करने के लिए मजबूर किया था। यहां तक कि अशोक कुमार से खाली कागज पर दस्तखत भी ले लिए गए थे। उसने प्रद्युम्न की हत्या की है। इस खुलासे के बाद से कई पुलिसकर्मी जांच के घेरे में आ गए हैं। उधर, हरियाणा के डीजीपी ने कहा था कि प्रद्युम्न मर्डर केस में हुई पुलिस जांच में कोई खामी नहीं है। हमने पूरी प्रामाणिकता जांच करने के बाद ही केस सीबीआई को सौंपा था। किसी अपराध के विश्लेषण के समान पर

परली का भूसा ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल में आता

प्रदूषण से बचने के लिये परली का भूसा और खाद बनाने का सुझाव

एजेंसी

नयी दिल्ली। केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण पंजाब में पराली जलाने के बाद पराली जलाए जाने के मुद्दे से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण अत्यंत दृष्टि की समस्या के समाधान के लिये परली के बहुउद्देशीय उपयोग की कार्ययोजना पर काम कर रहा है।

सीपी आयोग और सीआईआई की संयुक्त रिपोर्ट में परली के व्यावसायिक और पोस्ट इकोनॉमिक को कार्ययोजना पेश की गयी है। पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त सचिव ए के वेदना की अध्यक्षता में सीपी आयोग और सीआईआई के संयुक्त कार्यबल ने पंजाब में पराली के बहुउपयोग के तरीके सुझाते हुये इस बात को रेखांकित किया है कि पराली को जलाने की पराली को जलाने से किसानों को रोकने के लिये इसके दो उपयोग सुझाये गये हैं। पहला, पराली का भूसा बनाकर इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने और दूसरा, पराली से खाद बना कर किसानों को इसे सस्ता के लिये वित्तीय करना बेहतर तरीके हैं। कार्यबल ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा को गुणवत्ता के खराब होने में पराली को चुनौती के उपायों का पिछले साल नवंबर में अध्ययन शुरू किया था। इस साल जून तक पहले अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल पंजाब को करीब 45 करोड़ टन पराली आवशेष निकलता है। साल भर को पराली को डिस्पोजेबली दो करोड़ टन है। कमेटी ने पराली जलाने को किसानों की मजबूरी को स्वीकार करते हुये इसका बहुउपयोग सुनिश्चित करने के लिये उद्योग जगत से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की अपील पर बल दिया है। समिति ने संक्षेप रिपोर्ट में पराली को किसानों से खरीद सुनिश्चित करने और आर्थिक इकाईयों को बेच कर इसके बहुउपयोग के उपाय सुझाये हैं। पराली का चारा, एथनॉल उद्योगों के अलावा ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल में आता है। सरकार को औद्योगिक इकाईयों के सर्वेक्षण से पंजाब में क्षेत्र पर ही किसानों से पराली को उचित दाम पर खरीद सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है।

पूर्व सरकारो में छोटी-छोटी सी बात पर हो हल्ला मचाने वाली महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग भाजपा सरकार में गर्भवती महिलाओं और शिक्षकों के बहते लहू पे चुप्पी : क्यो

गांधीप्रतिमा के सामने गर्भवती महिला पर चली बर्बर लाठियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिक्षक दिवस के दिन जहां एक ओर शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बीएड टीईटी अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठिया बरसाई जा रही थी। लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे इस भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने महिला तथा पुरुष में फर्क भी नहीं किया बस जो सामने आता गया उसे लाठियां पड़ती गई। इसी बीच एक गर्भवती महिला के पेट पर पुलिस वाले ने लाठी मारी जिससे महिला दर्द के मारे कराह उठी। पुलिस की टीम आनन-फानन में महिला को पुलिस वैन में अस्पताल लेकर गई। बीएड टीईटी अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर इको गार्डन में बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने विधानसभा की तरफ कूच कर दिया। इस दौरान विधानसभा पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने अभ्यर्थियों को रोकने का प्रयास किया। इस गर्भवती महिला को देखकर साथी महिला अभ्यर्थी ने उसे संभाला। आनन फानन में महिला को पुलिस जीप में अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी

पुलिस वालों ने गर्भवती महिला के पेट पर मारी लाठी

बीएड टीईटी अभ्यर्थी कई दिनों तक राजधानी के हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। आश्वासन मिलने के बाद भी जब नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई तो एक बार फिर अभ्यर्थी इको गार्डन से विधानसभा का घेराव करने निकले। इसी दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हो गई जिसमें एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी घायल हो गई।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को सैकड़ों माध्यमिक विद्यविहीन शिक्षक अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन से निकलकर हजरतगंज स्थित जीपीओ जा पहुंचे, जिसका पुलिस को हवा तक नहीं लगी। इसके बाद सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करे थे। इस दौरान विद्यविहीन शिक्षक रेनु मिश्रा नाम की महिला ने बाल मुड़वाने के लिए बैठ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिस पहुंचकर समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक न सुनी, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी फटकार दिया, जिसमें कई लोग चोटिल भी हो गये।

इसके बाद पुलिस ने शिक्षकों को जबरन बसों में भरकर धरनास्थल भेज दिया गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्व मे मिलने वाले मानदेयों को बंद कर दिया है, जिससे शिक्षक सड़क पर आकर व भीख मांगने पर मजबूर। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एसएलसी उमेश द्विवेदी का कहना था कि हजारों की संख्या में मौजूद शिक्षक अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना व प्रदर्शन को रूप दे रहे है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में कार्यरत विद्यविहीन शिक्षकों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से समान कार्य समान वेतन का फायदा लागू कर उनको भुगतान जाए, साथ ही व्यवसायिक, कम्प्यूटर, पीटीए व अन्य शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेन्शन योजना अविलम्ब बहाल किया जाए जैसी अन्य मांगों को मानकर सरकार तत्काल शिक्षकों के हित में कदम उठाए। सरकार द्वारा मांगे न मानने की स्थित में शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक एक जुट होकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर भीख मांगकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के महासचिव अशोक कुमार राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री को जानकारी करने से पहले जानकारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जानकारी की जितनी निन्दा की जाय कम है।

अखिलेश यादव का आरोप-

योगी सरकार ने किया शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला, बदलीं गईं कापियां

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को कहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षक भर्तियों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया है, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, बीटीसी शिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भाजपा सरकार में नौकरियों को लेकर छल-कपट किया जा रहा है,शिक्षक भर्ती घोटाले के पीड़ितों के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अखिलेश ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में घांपली हुई है, लोकसभा चुनाव तक पेपर आउट कराना, भर्तियों को रद्द करना ही भाजपा की रणनीति है,भाजपा का यह कार्य छात्र-नौजवान विरोधी है, यह छात्रों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।

प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश को अपना ज्ञापन सौंपा, सदस्यों ने अखिलेश को 68,500 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता व बने हुए पदों पर नियुक्ति में आशंकाएं किए जाने से अवगत कराया, उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि 27 मई, 2018 को हुई 68,500 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 21 मई 2018 के सामनदेश में सामान्य, ओ.बी.सी. और एससी/एसटी का कटऑफ परीक्षा परिणाम में बदल दिया गया, जिसमें 41,556 अभ्यर्थी ही उत्तर्ण हुए, पूरी भर्ती प्रक्रिया में न केवल कॉपियों का गलत मूल्यांकन कर अनुत्तीर्ण किया गया, बल्कि कुछ अभ्यर्थियों की कॉपी भी बदल दी गई।

टिप्पणियां प्रतिनिधिमंडल ने बची हुई 27,000 सीटों को 21 मई के सामनदेश के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने और शिक्षक भर्ती की पूरी सीबीआई जांच की मांग की, दोषियों को दंडित किए जाने के लिए अखिलेश यादव से सहयोग किए जाने की भी उन्होंने अपील की है,अखिलेश ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया और कहा कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

दौरान उन्होंने जमकर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लाठियां भांजते समय पुलिस प्रशासन ने महिला और पुरुष की सारी सीमाएं पार करते हुए जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान एक पुलिस कर्मी ने तो गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा उस पर भी लाठी बरसा दी। पुलिसकर्मी की लाठी पड़ते ही महिला दर्द से कराहने लगी। इस बीच किसी भी पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। दर्द से कराहती

प्रदर्शन कर रहे दो सौ शिक्षक अभ्यर्थी गिरफ्तार

अभ्यर्थी हाथ जोड़ते रहे, पुलिस लाठी चलाती रही

लखनऊ। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को पुलिस ने रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया। रात तक गिरफ्तार अभ्यर्थियों को छोड़ा नहीं गया था। एसपी ट्रैफिक सुधा दी की तहरीर पर सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार सुबह नौ बजे से बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे अभ्यर्थी रविवार को भी डटे रहे। अभ्यर्थी 33 प्रतिशत कटऑफ पर परिणाम घोषित करने के साथ ही 68,500 सहायक अध्यापकों के सभी पदों को भरे जाने की मांग कर रहे थे। दोपहर बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों से परिसर खाली कराने का प्रयास किया तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके चलते पुलिस ने लाठियां भांजने में भी गुरेज नहीं किया। पुलिस ने शाम चार बजे निदेशालय परिसर खाली कराते हुए दो सौ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा बलपूर्वक निदेशालय खाली कराने पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने हाथ पांव जोड़े, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों पर लाठी भी भांजी जो परिसर खाली नहीं कर रहे थे।

बीती रात तीन बजे भी पुलिस ने अभ्यर्थियों से खदेड़खदेड़ कर निदेशालय परिसर को खाली कराने का प्रयास किया था, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के होने के चलते पुलिस को पांव पीछे खींचना पड़े। हालांकि कई महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप भी लगाया।

शिक्षक दिवस पर जामिया में अध्यापकों और कर्मचारियों ने इस वजह से किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। शिक्षक दिवस पर जामिया में टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों ने विरोध-प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना के खिलाफ सभी ने काली पट्टी बांधकर गलिब स्टैच्यू के सामने अपनी बात रखी. फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन ने आज देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था टिप्पणियां शिक्षक दिवस का ही दिन इसलिए चुना गया, ताकि यह बताया जा सके कि नई पेंशन और रिटायरी स्कीम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक और दूसरे कर्मचारी कितना परेशान हैं. जामिया टीचर्स एसोसिएशन (जुटा) के अध्यक्ष प्रोफेसर असीर आ रिव और सचिव प्रोफेसर माजिद जमील ने अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों को संबोधित किया और यह मांग उठाई कि सरकार नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करे.इस प्रदर्शन में जामिया स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एसआरके एसोसिएशन ने भी अपना सहयोग दिया।

सिर्फ संख्या से नहीं बन जाती है जनता - लेखपालों, शिक्षामित्रों समझ लीजिए...

शिक्षामित्र लाचार हैं, वे धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने-थाने फिर रहे हैं।हर दिन मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में विभूषन का मैसेज आ जाता है. एक लाश और उसके आस-पास रोती-बिलखती औरतों की तस्वीर होती है. उत्तर प्रदेश में ऐसी लाश को शिक्षामित्र कहते हैं, जिसके बीच जिन्दा लोगों की संख्या अब भी पौने दो लाख है। थाने वालों के कारण अलग-अलग हैं, मगर सदमा, दिल का दौरा और अवसाद के अलावा आत्महत्या भी वजह कारण हैं। शिक्षामित्र विभूषन जब इन मौतों को पचाकर लेकर मेरे दफ्तर आए, तो देर तक मोटी-सी यह फाइल दिखाते रहे। कभी किसी ने 100-200 लाशें कमरे में लाकर रख दी हों। खबर में दिखाने के बाद शिक्षामित्रों ने धन्यवाद का संदेश तो भेज दिया, लेकिन दिखाने के बाद हुआ क्या, इसका जवाब जीते हैं. कुछ नहीं हुआ. आज भी शिक्षामित्रों की लाश की तस्वीरें मेरे इनबॉक्स में आ रही हैं। विभूषन जैसे हजारों शिक्षामित्रों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।

शिक्षामित्रों ने 17-18 साल तक सरकार के स्कूलों में पढ़ाया है। सरकार ने इन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दिया है और अलग-अलग तरह के सरकारी काम भी लिए हैं। इनकी नौकरी पक्की भी हुई, मगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए, फैजान मुस्तफा ने खबर ली में कहा था कि इनका केस मजबूती से नहीं लड़ गया और कई पक्ष कमजोर नजर आते हैं, जबकि इनकी अपनी कोई कमी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि इनकी सैलरी 40,000से घटाकर 10,000 कर दी जाए, मगर तुरंत ही इनकी सैलरी 10,000 कर दी गई, जबकि अब भी ये सेवाएं दे रहे हैं। 17 साल की नौकरी में दो से तीन साल ही इन्हें 30,000 से 40,000 की सैलरी मिली है। उससे पहले ये 1,400 से 2,000 की सैलरी पर काम कर रहे थे. इतने कम पैसे में इनसे अंग्रेजी की कान्वेन्टिक पुलिसिंग की तरह गुणवत्ता की उम्मीद करने वाले भी चांद से हर रविवार पानी पर रुप देने आते होंगे। शिक्षामित्र लाचार हैं, वे धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने-थाने फिर रहे हैं और अंत में मर जाते हैं. कभी बीवी की मार से, कभी अपनी हताशा से. इनकी संख्या पौने दो लाख है, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र में अपने ही साथियों की लाश की तस्वीरें फ्रेमवर्क करते हुए भटक रहे हैं. जैसे की तैसी ने इन्हें इतना तोड़ दिया है कि बहुतों के मोबाइल में चार्ज का पैसा तक नहीं होता है.शिक्षामित्रों की बात करने पर कुछ मैसेज आने लगता है कि ये लोग चोर हैं, पढ़ते नहीं हैं. यह नहीं करते हैं, वह नहीं करते हैं, मगर किसी का एक मैसेज नहीं आता है कि इनकी हालत तो बहुत खराब है। इनके साथ हाल्य को ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक लेखपाल 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं. उनकी मांगें ऐसी नहीं हैं कि सरकार की तोड़कर लाने पड़ें। लेखपालों के बारे में दिखाने पर ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, ये जनता का खून चूसते हैं. आपको इनसे सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, एक तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसी जनसमूह को देखने का सही लोकेशन नहीं है, उनकी मांगों को हम उनके प्रति जनता के बीच छवि के चश्मे से नहीं देख सकते हैं।

फिर तो हमारे नेताओं को कौन-सी छवि ऐसी है कि हम उन्हें सत्ता सौंप देते हैं. ये लेखपाल के बारे में नहीं जानता था, लेखपालों को पता था कि आज का मीडिया पटवारी, अमीन और लेखपाल के बारे में नहीं जानता है, इसलिए एक लेखपाल ने जमघटकी की तरह एक लंबे-से कागज पर अपने 41 कार्यों की सूची लिखकर टांग दी, ताकि सब समझ सकें। लोग मीडिया से भी ज्यादा रचनात्मक हैं। कई लोगों ने काम करते हुए की तस्वीरें भेजीं, जिनके जरिये मैं देख सका कि लेखपाल चाहू, सुखाड़ू, आगजनी, ओलावृष्टि के वक्त जमीन से लेकर गांव तक की पैमाइश करते हैं, आंकड़ों को सबसे पहले सही खोजकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। कितने रकबे में फसल बोई गई है और कितनी हुई है, यह रिकार्ड भी लेखपालों के जरिये कृषि मंत्रालय तक जाता है. गांव की जमीनों की पैमाइश कागज और रिकॉर्ड सहना इनका ही काम है। सीटों की कमाई पर पटवारी व्यवस्था कई खामियों से ग्रस्त है, मगर इनका उपयोग है, यह इनके कामों को सूची से साबित तो होता ही है. अगर ये काम नहीं करते हैं तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि जमीन पर सरकार नहीं है। कोई काम ही नहीं करता है. अगर कोई काम करता है, तो उस काम का उचित मेहनताना मिलना चाहिए कि नहीं. सरकार दिनभर ताने कसती रहती है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, फिर उसके कर्मचारियों को मांग के साथ क्यों कहा जाता है कि ये ऊपर से कमा लेते हैं, तो फिर नीचे दिया गया पैसा ऊपर तक भी पहुंचता होगा. सरकारी कर्मचारियों को समझना होगा कि ये इस छवि से कैसे लड़ेंगे और ये नहीं लड़ेंगे, तो धरना देते रह जाएंगे, और होगा कुछ नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी चोर हैं, यह चाह जनता और सरकार तब क्यों कहती है, जब ये अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं। उन्हें चोर कहने वाले भी कम चोर नहीं हैं। मैंने कई तहसीलों के चौदिगे देखे, जो लेखपाल बंधुओं ने भी मेरे लिए भेजे, ताकि मैं देख सकूं कि ये कैसी जगहों पर काम करते हैं। जर्जर इमारतों के नीचे जमीन पर बिछे दरी पर काम कर रहे हैं. भरत 21वीं सदी में सुपरपॉवर और विश्वगुरु बनने जा रहा है... ! आपने किस सुपरपॉवर के पटवारी देखे हैं कि 30,000कर्मचारी बगमरे और पेड़ के नीचे बैठकर काम करते हैं। भारत भर में करोड़ों रुपये फूंककर स्वच्छता का विडियो पोस्ट गया, मगर सरकारी कार्यालयों में ही शौचालय नहीं है. उनकी साफ-सफाई को कोई व्यवस्था नहीं है। हम सब दलालों से यह देखते आ रहे हैं। लेखपाल भी अपनी इस हालत को जीते आए हैं, लेकिन बदलाव की चाह केवली है.लेखपालों को 2,000 का ग्रेड मिलता है, जो चाहत कम है. उन्हें जो पाड़ भत्ता मिलता है, उसे जानकर होली नहीं, रोना आएगा। 3 रुपये 33 पैसे प्रतिदिन पाड़ भत्ता मिलता है और इतना ही रोजहरी का पैसा दिया जाता है. क्या ये लोग अपनी जेब से या जनता की जेब से लेकर सरकार का काम नहीं कर रहे हैं... ? कब इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, क्या हमारी पिछली पीढ़ी के सबसे जरूरी कर्मचारियों के पैडले, पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्या उनके कमरे में पंखे भी नहीं होने चाहिए... ?दरअसल, इस लोकतंत्र में चाहत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की भीड़ चुन गई है, जो जनता को ही बर्बाद कर रही है। जनता को ही लगातार कह रही है कि तुम चोर हो। खुद को जनता समझने वाले लेखपाल, शिक्षामित्र और बीटीसी शिक्षक और बीटीसी उर्दू शिक्षक इन बातों को सिर्फ अपनी मांगों के संदर्भ में देखते हैं, मगर पूरी के संदर्भ में देखेंगे, तो खाक-खाक दिख जाएगा. जनता को यह देखना चाहिए कि सरकार उसी के साथ नहीं, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। जनता ही जनता से अलग हो जाएगी, तो फिर यह सरकार के सामने जनता नहीं रोएगी, बस कुछ लोगों को चोट रोएगी, जिसे कोई सियासी भी कलेक्टर के आदेश पर ताक आएगा। उत्तर प्रदेश में 12,460 बीटीसी शिक्षकों के बारे में कई बार कार्यालय किया कि कोर्ट से दो-दो बार जीतने के बाद भी सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है. इन लोगों का सबसे दोहरा, इन्होंने एक बार भी मुंह नहीं कहा कि उन्हें के साथ 4,000 उर्दू शिक्षक भी हैं और ये भी उन्हीं की तरह कोर्ट से केस जीत का नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दोनों का विज्ञापन एक साथ निकाला था, दोनों का मामला एक है। 12,460 शिक्षकों ने आवाजें से 4,000 उर्दू शिक्षकों को आगे कर दिया। मुसलमान समाजकर किया या पहले अपना देखने के तहत किया, मैं इसे लेकर गेस नहीं कारण चाहता, मगर 4,000 उर्दू शिक्षकों में से 30 प्रतिशत गैर-मुस्लिम भी हैं और 12,460 बीटीसी शिक्षकों में से मुस्लिम भी हैं। क्या पता, उर्दू शिक्षकों ने ही खुद को आगे कर लिया हो कि अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगे, मेरे पास इसके बारे में सारे तथ्य नहीं हैं।

मैंने 12,460 बीटीसी शिक्षकों और 4,000 बीटीसी उर्दू शिक्षकों का उदाहरण इसलिए दिया, ताकि आप समझ सकें कि जनता टुकड़ों-टुकड़ों में जनता नहीं हो सकती, यह सही है कि इन 16,460 शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त संघर्ष किया है, हर जिले में भारत प्रदर्शन किया है और लाठियां खाई हैं। फिर भी ये अपनी पूरी लड़ाई नहीं जीत पाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद भी और कोर्ट के चार हफ्ते में नियुक्ति पत्र देने के आदेश के बाद भी सबको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है. करीब 5,000 को ही नियुक्ति पत्र मिला है और अब भी 12,000 के करीब नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं. अभी भी दोनों मिलकर नहीं लड़ रहे हैं. जिस जनता के दम पर ये वेतन जीतकर सरकार बना लेते हैं, उस सरकार के सामने जनता लगातार हार रही है। उसका जनता बनना बाकी है. यह धार्मिक उन्माद, जातिवादी आंकिका के पीछे दौड़कर खुद को जनता समझती रहे, मगर जब भी यह आवाज उठाएगी, कुचल दी जाएगी, पौने दो लाख शिक्षामित्रों, 30,000 लेखपालों और 12,000 शिक्षकों को सोचना चाहिए कि ये अपनी लड़ाई अलग क्यों लड़ रहे हैं, क्या उनकी सहानुभूति एक दूसरे से है, इस सवाल का ईमानदार जवाब उनके लिए बेहतर भविष्य की दिशा तय करेगा।

टिप्पणियां इन सबको ईमानदारी से एक और सवाल पर गौर करना चाहिए, अंग्रेजीकाल पर जाने से पहले ये किस तरह की सड़कों के गले में थे, क्या ये पत्रकारिता के फैलने पर की जाने वाली सड़कों के प्रति सर्वाधिक थे या उनके चश्मों को ऐसाई चश्म देने के लिए चाय रही टिप्पू-सुलियम चाहमें में चाह रहे थे, आज अंग्रेजों जनता नहीं बन सकते और अंग्रेजों हो ट्रांसफर करके सड़कों पर छाया नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ पत्रकारिता की पैरिकाता से हो, इसे प्रश्न करने में ट्रांसफर करके आपने जो भूमिका अदा की है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, किसे पलवाद है कि 17 और 18 जुलाई को रेलवे के लोकोपायलट भूखे पेट गाड़ी चलाएंगे, ये काम करते हुए अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आप चैनलों से उम्मीद करते हैं, तो कहाए, आप इस उम्मीद से पहले क्या देखते रहे हैं।

लखनऊ से प्रकाशित.....

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

6AM

न्यूज टाइम्स

लखनऊ 28 दिसंबर दिन गुरुवार 2017

वर्ष:1 – अंक:41 | पृष्ठ:8 – मूल्य: 2 रुपए

Email.6amnewstimes2188@gmail.com

राफेल सौदे में बातचीत से देश को काफी बचत हुई: निर्मला

3 बीजेपी की गतिविधि के लिये इस्तेमाल किया जा रहा प्रधानमंत्री निवास : मायावती

8 अखिलेश यादव ने दी अच्छी विदेश नीति अपनाने की सलाह

राजनैतिक द्वेष के शिकार हैं लालू?

लालू यादव के बीजेपी से समझौता कर हाथ मिलाने पर, तेजस्वी यादव ने किया बड़ा खुलासा ?

पटना। राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि अगर लालू जी आज अपने डीएनए मे समझौता कर लें और हाथ मिला लें तब आप देखिए ये चारा घोटाला भाईचारा घोटाला और लालू यादव राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे. लेकिन उनका कहना हैं कि भाजपा के सामने झुकने का सवाल नहीं हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद पूरी दिलेरी से सच को राह पर अड़े हैं. तथाकथित चारा घोटाला दो मिनट में भाईचारा घोटाला में तब्दील हो जाता अगर लालू प्रसाद का डीएनए बदल जाता। अगर लालू प्रसाद बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वह हिन्दुस्तान के आज के राजा हरिश्चंद्र होते. तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हर सूरत में सिद्धांतों पर चलने के हठ के सामने लालू प्रसाद की तरह कोई दूसरा नहीं है. उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि लालू यादव और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह भाजपा के विरोध का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद को फंसाया गया है, तथाकथित भ्रष्टाचार तो बहाना है. विरोधियों द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भी अपशब्द कहे जाते रहे, जबकि उन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं था.तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू को सजा होने पर बिहार की जनता खासा नाराज है और वो इसका विरोध कर रही है. तेजस्वी ने कहा कि उन लोगों को ये जानकारी पूरे राज्य मे मिल रही है कि लोगों में लालू यादव के साथ जो हो रहा हैं उसके प्रति काफी आक्रोश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जिनको लोगों ने चुना है वह कारागार में हैं और जिनको जनता ने नहीं चुना वह सरकार में हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी को फंसाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। वो जानते थे कि लालू जी अगर रहेंगे तो नीतीश कुमार कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बन सकेंगे. नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लालू जी के खिलाफ साजिश की है. हालांकि तेजस्वी के अनुसार नीतीश कुमार और भाजपा को समझना चाहिए कि लालू जी को जेल भेजकर खतरा टला नहीं, बल्कि एक नया काल पैदा हो गया है.उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती। वह हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है. बीजेपी के राज में देश में अघोषित रूप से एमरजेंसी है. सरकार के खिलाफ बोलने वाले पर झूठे मुकदमे होते हैं. ऐसे कई उदाहरण हैं. यह सरकार तानाशाह है. संविधान और हमारा देश खतरे में है. हमारा फर्ज है कि हम संविधान की रक्षा करें. तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है और वह प्रोपगैंडा बनाने में माहिर है.किया है, उसके खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करना है. इन लोगों से हमलोग डरने वाले नहीं हैं। अपनी विचारधारा से हमने कभी समझौता नहीं किया. तेजस्वी ने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं और इसी प्रक्रिया में लालू प्रसाद दोषमुक्त भी होंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष को रोका जा सकता है, उसके विचारों, मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प को नहीं. राजद ने अपने सभी ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष को 6 जनवरी को पटना में एक बैठक में बुलाया है। बैठक में राजद अध्यक्ष लालू यादव के चारा घोटाले में सजा होने के बाद की स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

✔ बीजेपी के राज में देश में अघोषित रूप से एमरजेंसी है: तेजस्वी

व्यापमं पर कार्रवाई क्यों नहीं : तारिक अनवर

कटिहार। राकांपा के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने आज आरोप लगाया कि चारा घोटाले के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषसिद्धि 'राजनैतिक द्वेष' का नतीजा है और सीबीआई ने 'दबाव में काम किया' है.राकांपा नेता रांची में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद और 15 अन्य को दोषी ठहराने पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत छह अन्य को बरी भी कर दिया था.तारिक अनवर ने संवाददाताओं से कहा, ''जो कुछ भी लालू प्रसाद के साथ हुआ है, वह राजनैतिक द्वेष का नतीजा है। लेकिन जब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वह अपील करेंगे तो उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी।'' अनवर ने आरोप लगाया, ''मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापमं घोटाला हुआ है। लेकिन हमने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं देखी।''उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुजरात में अपनी सत्ता भले ही कायम रखी हो, लेकिन विधानसभा में उसकी सीटों की संख्या में काफी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य के नतीजे सभी विपक्षी दलों के लिये सबक हैं कि वे अपने मतभेद भुला दें और सांप्रदायिक शक्तियों से मिलकर लड़ें।

हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर ने ली शपथ

शिमला। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित समारोह के दौरान आज हिमाचल प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठाकुर के साथ उनके मंत्रिमंडल के 11 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली।हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 52 वर्षीय ठाकुर और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। स्वयं सेराज से छठी बार भाजपा विधायक चुने गये ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल में छह नये चेहरों को शामिल किया है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कई अन्य केन्द्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही 12 सदस्यीय कैबिनेट की संख्या पूरी हो गयी है। दो अन्य विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया है।हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 74 राजीव बिंदल होंगे। ठाकुर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले मंडी से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं।

वह राज्य के 14वें मुख्यमंत्री और प्रदेश में इस पद पर आसीन होने वाले छठे व्यक्ति हैं। समारोह के दौरान सुरेश भारद्वाज और गोविंद सिंह ठाकुर ने संस्कृत में, जबकि अन्य ने हिन्दी में शपथ ली। ठाकुर की कैबिनेट में एक मात्र महिला चेहरा है सरवीन चौधरी।ठाकुर के मंत्रिमंडल में शामिल 11 मंत्री हैं मोहिन्दर सिंह, कृष्ण कपूर, सुरेश भारद्वाज, अनिल शर्मा, सरवीन चौधरी, राम लाल मारकंडा, विपिन परमार, वीरेन्द्र कंवर, गोविन्द सिंह ठाकुर, राजीव सैजल और विक्रम सिंह। कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा उनके गृह जिला मंडी से दो और मंत्री शामिल हैं। सबसे बड़े कांगड़ा जिले से चार जबकि शिमला, सोलन, कुल्लू, ऊना और लाहौल-स्पीति से एक-एक विधायक को मंत्री बनाया गया है।

✔ ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल में छह नये चेहरों को शामिल किया है

केजरीवाल सरकार के सामने आई कई चुनौतियां

नयी दिल्ली। दिल्ली में आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच पिछले साल के मुकाबले इस साल कम टकराव देखा गया लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार को प्रदूषण, अधूरे चुनावी वादों और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों से दो-चार होना पड़ा। पिछले साल 31 दिसंबर को राज निवास का प्रभार संभालने के बाद अनिल बैजल ने नए न्यूनतम वेतन और शिक्षा ऋण योजना जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार के कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।बैजल के पूर्ववर्ती नजीब जंग और आप सरकार के बीच नौकरशाही पर प्रशासनिक नियंत्रण समेत कई मामलों को लेकर टकराव होता रहता था। बहरहाल, अन्नूर में कई मौकों पर उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच तकरार देखने को मिली। केजरीवाल ने करीब 17,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के सरकार के फैसलों को मंजूरी देने में बैजल की ओर से की जा रही देरी पर कहा था कि ''वह निर्वाचित मुख्यमंत्री है ना कि आतंकवादी।

अखिलेश यादव ने सैफई के अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईजीसीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का किया उद्घाटन

2019 के लोकसभा चुनाव के लिए, अभी से जुट जाएं सपा कार्यकर्ता: अखिलेश

इटावा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी कार्यकर्ताओं से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने की अपील की है। यह बात अखिलेश यादव ने सैफई में को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईजीसीएल के उद्घाटन के समय कही।अखिलेश यादव ने सैफई के अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुई आईजीसीएल (इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग) क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता के सभी मैच डे नाइट होंगे।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा ही देश और प्रदेश को आगे ले जाएगी।अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से मुस्तैदी से जुट जाएं क्यों कि जो हालात भाजपा वालों ने आम लोगों के बना दिए है उससे एक बात साफ हो गई है कि 2019 में भाजपा को खाली हाथ लौटना पड़ेगा।सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2022 में युवाओं को सपा के साथ खड़े होकर ताकत दिखानी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी 2022 के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि 2019 के ही चुनाव में देश की सत्ता में वापसी की कमर कस चुके हैं।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुये कहा कि भाजपा वालों से सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा वालों का गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया। भाजपा वाले हर चीज को आधार से जोड़ रहे हैं। हम कह रहे है कि देश के युवाओं को भी आधार से जोड़ दो ताकि इनको कम से कम रोजगार तो मिल ही जाये। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित ही देश से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी ।उन्होंने कहा कि मोबाइल के माध्यम से चल रही सोशल मीडिया की खबरों से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित भाग ले रहीं टीमों के खिलाड़ियों व अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये बीजेपी वाले मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया का जमकर प्रयोग कर रहे हैं।

इसलिए सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास मत करना।उन्होंने अपने खिलाड़ी जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि आज आपको बहुत ही बेहतर गेंद से क्रिकेट खेलने को मिल रहा है लेकिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो इससे बहुत खराब गेंद हुआ करती थी। आप लोग तो इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम में आनंद ले रहे हैं लेकिन हमारे समय में तो खेल का कोई मैदान ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आज आईजीसीएल के माध्यम से क्रिकेट को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है।अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा- ग्रामीण इलाकों में खेल को बढ़ावा देना देश की खेल प्रतिभाओं के लिए अति आवश्यक है। सैफई में 'दूसरा' इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग' का शुभारंभ करते हुए।आईजीसीएल के उद्घाटन समारोह में, अखिलेश यादव खुद बल्ला थामकर मैदान में बैटिंग करने उतरे। इस दौरान अखिलेश यादव को मैदान में देखकर लोग काफी उत्साहित भी दिखे।अनुपमा बैंड ने ऐसा समा बांधा की खिलाड़ी व दर्शक झूमते रहे।बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुपमा राग व उनकी सहयोगी अमन तृषा ने लाल दुपट्टा, शालू के नुमके, तेरी गलियां, चाप का माल, नजर से नजर मिली, रंगी साड़ी गुलाबी, नैना रे, आदि गीत सुनाए। आईजीसीएल के उद्घाटन में सपेरों की एक टोली भी खूब नाची। उन्होंने बीन बजाकर नृत्य किया।

✔ कहा, 2022 में युवाओं को सपा के साथ खड़े होकर ताकत दिखानी है

लखनऊ से प्रकाशित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

6AM न्यूज टाइम्स

RNI.No.UPHIN/2017/75301

लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज में प्रसारित...

तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य अभी धुंधला ...04

गोल्डन एज में ओल्ड बनाए डिप्रैशन..07

वर्ष -9 अंक- 74 E-mail : 6amnewstimes2188@gmailcom लखनऊ, शनिवार, 7 फरवरी 2026 मूल्य 8.00 रुपये

नाबालिग लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमतिः एससी

6AM NEWS TIMES

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में एक नाबालिग लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अदालत किसी महिला को, और विशेष रूप से एक नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने जोर देकर कहा कि गर्भवती लड़की को बच्चे को जन्म देने या नहीं देने के उसके अधिकार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसका मन नहीं हो

कि वह बच्चे को जन्म दे और ऐसी इच्छा उसने साफ साफ शब्दों में बार बार जाहिर भी की हो। पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एक नाबालिग को ऐसी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उसकी मर्जी के बिना है। अदालत ने कहा, अदालत किसी भी महिला को, नाबालिग बच्चे की तो बात ही छोड़िए, अपनी गर्भावस्था पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, अगर उसका ऐसा करने का इरादा ही नहीं हो।न्यायालय ने माना कि यह मामला इस पर निर्भर नहीं करता कि गर्भधारण सहमति से बने संबंधों के कारण हुआ था या दुष्कर्म से। वास्तव में फैसला इस बात से तय होना कि नाबालिग की यह स्पष्ट इच्छा क्या है और उसका मन यही है कि वह बच्चे को जन्म न दे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्वीकार किया कि हालांकि एक बच्चे का जन्म अंततः एक जिंदगी को दुनिया में लाता है, लेकिन इस मामले में नाबालिग की स्पष्ट अनिच्छा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के जेजे अस्पताल को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक चिकित्सा संबंधी उपायों का पालन करते हुए गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन की प्रक्रिया शुरू करें।

यह फैसला भारत में गर्भपात कानून के तहत स्वप्रजनन अधिकारों की व्याख्या में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। कारण यह है कि 24 सप्ताह की कानूनी सीमा के बाद भी विशेष परिस्थितियों में अदालत ने इस लड़की की पसंद को प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार गर्भपात की समय सीमा को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित किया गया है।सामान्य परिस्थितियों में सभी महिलाओं के लिए 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति है, मगर इसके लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। विशेष श्रेणियों की महिलाओं जैसे कि दुष्कर्म का शिकार बनी लड़कियां, नाबालिग, विधवाओं, दिव्यांगों या गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाओं के लिए यह सीमा 24 सप्ताह तक निर्धारित है और इसके लिए दो डॉक्टरों की इजाजत अनिवार्य है। यदि गर्भ में पल रहे भ्रूण को गंभीर बीमारी है, तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला के जीवन को तात्कालिक कोई गंभीर खतरा हो, तो कानून की किसी भी समय सीमा के बिना आपातकालीन स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जाती है।

सीमांत नगालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन का समझौता ऐतिहासिकः पीएम मोदी

- एफएनटीए को 46 विषयों से जुड़े मामलों में अधिकार सौंपे जाएंगे
- यह समझौता पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति और समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम है

6AM NEWS TIMES

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सीमांत नगालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण (एफएनटीए) के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ऐतिहासिक है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति एवं समावेशी विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक समझौता है, जो विशेष रूप से पूर्वी नगालैंड के विकास को गति प्रदान करेगा। केंद्र सरकार ने पूर्वी नगालैंड की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से सीमांत नगालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन के बारे नगालैंड सरकार और ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि इससे लोगों के लिए अवसरों और समृद्धि के नये द्वार खुलेंगे। यह पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति और समावेशी विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौते पर बृहस्पतिवार को नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

परीक्षा पे चर्चा को लेकर बोले सीएम योगी बोले-

पीएम मोदी के शब्दों में हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा

6AM NEWS TIMES

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में सकारात्मक दृष्टि, लक्ष्य की स्पष्टता और हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करने की प्रेरणा समाहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परीक्षा आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य की कसौटी होती है। ऐसे क्षणों में सही मार्गदर्शन विद्यार्थियों के मन से भय हटाकर उन्हें विश्वास और ऊर्जा भर देता है। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों से आत्मीय संवाद किया। सीएम योगी ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री ने छात्रों को यह संदेश दिया कि तनाव नहीं, संतुलन को अपनाइए; प्रतिस्पर्धा नहीं, आत्म-विकास पर ध्यान दीजिए और परिणाम नहीं, निरंतर प्रयास पर भरोसा रखिए। उनके शब्दों में सकारात्मक दृष्टि, लक्ष्य की स्पष्टता और हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करने की प्रेरणा समाहित है। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पोस्ट में लिखा, यह संवाद केवल परीक्षा कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में स्थिर रहने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने सामर्थ्य पर विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। निश्चय ही यह पहल करोड़ों विद्यार्थियों के मन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नए विश्वास का संचार करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी आभार व्यक्त किया और सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य, आत्मविश्वासपूर्ण प्रयास और सफलता से भरे पथ की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड शुक्रवार को जारी हुआ। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने आपका स्ट्रेस-आपकी गति से लेकर तनाव के साथ तैयारी, कम प्रेशर-ज्यादा शोरगुल, शोर के बीच टिके रहना और बड़े सपने-बड़े काम तक अलग-अलग विषयों पर छात्रों से संवाद किया। इसी बीच, उन्होंने छात्रों के कई सवालों के भी जवाब दिए। पीएम मोदी ने मार्क्स, रेंक्स और होने के बीच बैलेंस पर भी छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में पीएम मोदी के सामने गीत और कविता से लेकर खांसी भगाने तक छात्रों ने भी कई एक्टिविटी की।

न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगाः योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार के भगत भगत भीर, सप्त सरोवर रोड के पास सप्तऋषि आश्रम छावनी में संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी अब एक पिछड़ा राज्य नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। यूपी की बेहतर कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगे और कर्फ्यू से मुक्त होकर तेजी से विकास कर रहा है। सीएम ने कहा कि यही विश्वास का भटीनाथ धाम, केदारनाथ केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, ये राष्ट्र चेतना के केंद्र हैं। राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है। भटीनाथ धाम और केदारनाथ धाम सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र नहीं हैं बल्कि सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र को यहीं से शक्ति मिलती है। हमने इन केंद्र बिंदुओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। हमने इसकी विरासत का सम्मान किया है। उसकी रक्षा की है। नतीजा है कि एक समय बीमारू राज्य रहा उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। प्रगति के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।अब यूपी में अराजकता नहीं है। अब दंगे फसाद नहीं हैं। गुंडागर्दी नहीं है। चारों ओर कानून का राज यूपी में अब सब चंगा।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड में यहां पर भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के अंदर हम लोगों ने व्यापक परिवर्तन देखा है। यह निर्णय की यह शक्ति है जिसका सैकड़ों वर्षों से इंतजार था। भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है। यह चेतन परंपरा की साक्षात चेतना का भी केंद्र है। यहां संस्कृति केवल आस्था नहीं, एक पूरा जीवन दर्शन है।इस कड़ी में मैं कहता हूं कि भारत केवल एक तिथि में नहीं बना है। भारत किसी एक सत्ता की देन नहीं है। सनातन चेतना से इसका सनातनिक प्रवाह है। चेतना का परिणाम हमें सुप्रीम कोर्ट पर भगवे झंडे के तौर पर दिखता है कि यहां धर्मनिरपेक्षता तभी जायज मानी जाती धर्म है नहीं विजय है। भारत का उच्चतम न्यायालय भी इस बात को अंगीकार करता है। धर्म कभी कमजोर नहीं होता है, जो जानबूझ कर कमजोर किया जाता है। जो राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति को त्यागता है, वह न वर्तमान को सुरक्षित रख पाता है और न भविष्य को संजो पाता है। वैदिक भारत एक आत्मनिर्भर सभ्यता का प्रतीक है। आक्रांताओं के आने से पहले भारत केवल एक भूभाग नहीं था। वह पूर्ण विकसित सभ्यता, संस्कृति थी। यह राष्ट्र हमारे ऋषियों की तपस्या, किसानों के श्रम से और कारीगरों की कुशलनीतता के साथ खड़ा हुआ था।

यूजीसी कानून के समर्थन में हजारों संगठनों की रैलियों से उड़ने लगीं सरकार की नींद

रविन्द्र यादव

6AM NEWS TIMES

लखनऊ। विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को जाति भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त बनाने के लिए यूजीसी गाइडलाइंस अनिवार्य करना जरूरी, उत्तर प्रदेश बिहार सहित देश के सभी हिस्सों में दिन प्रतिदिन बढ़ते धरना प्रदर्शन से केन्द्र सरकार के साथ प्रदेश सरकारों की बढ़ती चिंता।

यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर 2 फरवरी से आज तक लगातार सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकालकर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप रहे हैं। जगदेव प्रसाद की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी गाइडलाइंस लागू करो, जाति जनगणना कराओ, न्याय पालिका में प्रतिनिधित्व की गारंटी करो, रोहित वेमुला अमर रहें, पायल तड़वी अमर रहें के नारे सरकार और यूजीसी विरोधियों की नाक में दम कर रहे हैं। यूजीसी के अपने आंकड़े ही बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस लिहाज से विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को जाति भेदभाव व उत्पीड़न से मुक्त बनाने की दिशा में यूजीसी इक्विटी नियमावली न्यूनतम कोशिश है। इसे तत्काल लागू किया जाए। सामाजिक न्याय के लिए ठोस व सुसंगत नीतियां व योजनाएं बने, इसके लिए जरूरी है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना की घोषणा के बाद अभी जाति जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं है, जाति जनगणना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि यूजीसी द्वारा लाया गया प्रगतिशील और समानता आधारित इक्विटी रेगुलेशन 2026 देशभर के विश्वविद्यालयों में समानता से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव व उत्पीड़न को रोकने के लिए एक्ट को संसद से पारित करने की मांग की। साथ ही जनगणना में जाति कॉलम जोड़कर जातिगत जनगणना कराए जाने की भी मांग उठाई। परिसरमें सौहार्दिक वातावरण सुनिश्चित हो सके छात्र नेताओं ने कहा कि सभी केंद्रीय, राज्य और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए और इसमें आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह पालन हो, ताकि सामाजिक न्याय, समान अवसर और परिसामपी सौहार्दिक वातावरण सुनिश्चित हो सके। छात्रों ने कहा कि कैंपसों में भेदभाव को खत्म करने की संपूर्ण जिम्मेदारी यूजीसी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों के दबाव में आकर नियमावली पर रोक लगाई है। सरकार से मांग की गई कि संसद में यूजीसी एक्ट लाकर इसे पास कराया जाए, ताकि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को न्याय मिल सके। संस्थागत हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नहीं, छात्र छात्राओं ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों पर हो रहे संस्थागत हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने इसे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम बताया और सुप्रीम कोर्ट से रेट हटाकर पुनर्विचार की अपील की।

देश भर में लाखों युवा छात्र छात्राओं के साथ अधिवक्ताओं और समाजसेवी यूजीसी के समर्थन में उतरे सड़कों पर

अब ना बीहड़ जंगल का डर ना बाढ़ का खतरा

योगी ने बदली पूरे गाँव वालों की जिंदगी 15 -15 लाख के साथ सबको पक्का मकान

6AM NEWS TIMES

बहराइच। अब ना जंगल का डर ना बाढ़ का खतरा , बैंक खाते में भी 15 लाख, सीएम योगी ने बदली भरतपुर के लोगों की जिंदगी जंगल के बीच रहने वाले 136 परिवारों के लिए खुशखबरी, 15 15 लाख के बाद अब पक्का घर भी देंगे योगी।

बहराइच मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर सतोंडीपुर सीमा जो नेपाल बॉर्डर के सघोर तराई में बसा भरथापुर गांव चहों ओर से जंगल, नेपाल और कौड़ीयाला नदियों से घिरा हुआ है।

अब योगी सरकार तोहफा देगी।

देश की आजादी से पहले से बसे भरतापुर गांव के लोगों का विस्थापन किया जा रहा है। यह गांव तीन तरफ पानी और एक तरफ जंगल से घिरा हुआ है।तीन तरफ पानी और एक तरफ जंगल... एक ऐसा गांव, जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क या रास्ता तक नहीं, लेकिन, अब बहराइच के इस गांव के लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है। भरतापुर के विस्थापन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ही घोषणा की थी। विस्थापन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, सर्वे-समाई का काम भी पूरा हो गया है। साथ ही सरकार से मिलने वाला पैसा कुछ लोगों के बैंक खाते में पहुंच गया है। तीन तरफ नदी व एक तरफ जंगल से घिरे टापू सरीखे नेपाल सीमा से सटे भरथापुर गांव के 136 प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सेमरहना गांव में सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी बनाकर बसाने के क्रम में आवंटन प्रक्रिया की बृहस्पतिवार को औपचारिक शुरुआत कर दी गई।

बहराइच का भरतापुर गांव आजादी से पहले का बसा हुआ है। इस बड़े बदलाव को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी खुद आने वाले हैं और इसके लिए हेलीपैड भी बनकर तैयार हो गया है। प्रशासन और वन विभाग ने जिन पात्र लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें 136 लोगों के नाम हैं। इनमें से 118 लोगों के खातों में रकम पहुंच गई है। प्रशासन की लिस्ट के हिसाब से सिर्फ 18 लोग ऐसे बचे हैं, जिनके खाते में पैसा जाना बाकी है।